अनुमान है कि रबी 1994 के दौरान लगभग 125 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली होगी । रबी फसल से खरीदे गए गेहूं के स्टाक के भण्डारण के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं । इसके अलावा, निगम ने सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धको/जोनल प्रबन्धकों को उस क्षेत्र में स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्षमता (ढकी हुई और कैप) किराए पर लेने की शक्तियां प्रदान की हैं । अत: वहां भण्डारण की कोई समस्या नहीं होगी । तथापि, निगम इस संबंध में सभी प्रयास कर रहा है और रबी स्टाक पर गहरी निगरानी रख रहा है ।

(छ) और (ज) भारतीय खाद्य निगम से सुगम स्टाक स्थिति को दृष्टि में केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के संबंध में एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में अपना जायजा लगाते हुए एक नोट प्रस्तुत किया है । सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

News item 'CWC strikes deals with corporates'

7161. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the 'Economic Times' dated the 29th March, 1994 under the caption "CWC strikes deals with corporates";

(b) if so, what are the reasons for this shift in policy;

(c) what are the details of the scheme including the terms and conditions thereof; and

(d) whether some agreements have already been entertd into in this regard; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes, Sir. There is no shift in the policy of Central Warehousing Corporation. The Corporation provides storage facilities for agricultural produce, foodgrains fertilisers, notified commodities such as industrial and consumer goods in its Warehouses. The companies referred to in the newspaper report have only kept their goods in the warehouses belonging to the Central Warehousing Corporation.

(c) and (d) There is no scheme as such. However, the Central Warehousing Corporation has entered into long term agreements with some private companies for storing their commodities/products in the warehouses of the Corporation. It has been stipulated that though the godowns will be used by the companies, the security for the godowns will be provided by Central Warehousing Corporation. The stocks will be kept in the godowns under the double locking system—one by Central Warehousing Corporation and the other by the depositors. The Insurance and accounting of the stocks will be that of the companies themselves. By providing such storage facilities, the Corporation has been able to augment its income.

गेहूं के निर्यात के संबंध में भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव

7162. श्री सोमपाल :
श्री शारदा महन्ती :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम चालू वर्ष में गेहूं के निर्यात पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानत: कितनी कीमत प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) गेहूं की किन-किन किस्मों का निर्यात किया जाएगा ;

(घ) गेहूं के निर्यात का देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है और

(ङ) गेहूं के निर्यात से गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों को क्या लाभ मिलेगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम से सुखम स्टाक स्थिति की दृष्टि में केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के संबंध में अपना जायजा लगाते हुए एक नोट प्रस्तुत किया है । सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Import/Export of sugar

7163. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the quantity of sugar exported every year, particularly in the year 1990, 1991, 1992 and 1993;

(b) what is the total amount of sugar imported from other countries to meet the growing demand of the public; and

(c) if the production is self-sufficient by when Government propose to stop export of sugar to other countries taking into consideration the piquant situation India faces?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) As per information received from the Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd., a designated Export Agency, the quantity of sugar exported during the financial years 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 was as under:—

Year	Quantity (in Metric Tonne)
1990-91 . . .	22176
1991-92 . . .	483137
1992-93 . . .	362662
1993-94 . . .	285192

(b) With a view to augment supply of sugar in the domestic market and to keep prices under check, Government has allowed import of sugar under Open General Licence. The total quantity of sugar imported/ to be imported would depend upon the contracts made by the individual firms/parties. Government has no role to play in these imports.

(c) Keeping in view the decline in production and limited availability of sugar for domestic consumption, Government has decided not to undertake any further export of sugar, excepting preferential quota to USA and EEC and a small quantity of sugar to Nepal under the Indo-Nepal Treaty a Trade.

चीनी का आयात

7164. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी का आयात करने की घोषणा की है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चीनी के आयात की सुविधा की घोषणा करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और